मगर इस बीच कुंभ मेला प्रशासन की ओर से गंभीर लापरवाही देखने को मिली, और 29 जनवरी, 2025 को हुई भगदड़ में कई दर्जन श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह से पहले हुई इस भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ के असल कारणों का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था, यदि पुलिस और प्रशासन वीआईपी मेहमानों को प्राथमिकता देने के बजाय आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता।

कुछ विशेषज्ञों ने यह भी टिप्पणी की है कि मेले में करोड़ों लोगों को बुलाने के लिए प्रचार तो खूब किया गया, लेकिन प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या कुंभ मेले में उपयुक्त बुनियादी ढांचा मौजूद है या नहीं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी ने मेले के बेहतर आयोजन के लिए विशेषज्ञों की राय लेने की बजाय अपनी पीआर टीम की बात अधिक सुनी।

मेले की अव्यवस्था का प्रभाव केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में कुंभ के कारण ट्रेनों में भीषण भीड़ देखी गई, जिससे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से समझौता करना पड़ा। इतना ही नहीं, कई विपक्षी दलों ने यह आरोप भी लगाया कि कुंभ मेले में मरने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को दबाने की कोशिश की गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 फरवरी, 2025 को संसद में कहा कि कुंभ में हजारों लोगों की जान गई है। हालांकि मृतकों की सटीक संख्या को लेकर आरोप–प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस भगदड़ ने यह साबित कर दिया कि आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकारें आज भी पूरी तरह गंभीर नहीं हैं।

यह भी दुखद है कि महाकुंभ के अवसर पर सस्ती राजनीति हो रही है, लेकिन नदियों के प्रदूषण को दूर करने के सवाल पर सत्ता वर्ग पूरी तरह खामोश है। सत्ता पक्ष यह प्रचारित करने में सबसे आगे है कि हिंदुओं के लिए नदियाँ "पवित्र" हैं और वे "माँ" के समान हैं। मगर इस पर चर्चा नहीं हो रही कि यदि नदियाँ पवित्र हैं और हिंदू समाज उन्हें अपनी माँ मानता है, तो वर्षों से इन्हें प्रदूषित क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों उद्योगों और शहरों के गंदे एवं जहरीले पानी को इन नदियों में डाला जा रहा है? यह कैसी भक्ति है कि हम नदियों को पवित्र मानते हुए उनमें स्नान करने के लिए भव्य मेले का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जो इन नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं? कुंभ मेले में मीडिया को कम से कम नदियों के प्रदूषण के सवाल को उठाना चाहिए था। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकार अब तक गंगा और अन्य नदियों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन नतीजा यह है कि ये नदियाँ आज भी गंदे नाले की तरह दिख रही हैं।

यदि नदियाँ हिंदुओं के लिए पवित्र हैं, तो क्या उन नदियों में रहने वाली मछलियों का उन पर कोई अधिकार नहीं? क्या प्रदूषण के कारण मछलियों की जानें नहीं जा रही हैं? यदि हिंदू समाज के नेता दया, शांति और सहिष्णुता की बात करता है, तो यही भाव नदियों को लेकर सरकारी नीतियों में क्यों नहीं दिखता? विकसित देश अब समझ चुके हैं कि नदियों को गंदा रखने के क्या नुकसान हैं। उन्होंने अपनी कई नदियों को साफ कर दिया है और बड़े–बड़े बांध बनाने की पुरानी नीति को बदल दिया है। अब उनकी सोच बदल गई है, और वे समझ चुके हैं कि नदियों को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाए और उनमें जहरीला कचरा न डाला जाए। लेकिन भारत के राजनेता एक तरफ तो नदियों को पवित्र कहते हैं और दूसरी तरफ उनके प्रदूषण पर चुप्पी साधे हुए हैं। दुख की बात यह भी है कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी मुख्यधारा की मीडिया से पूरी तरह गायब रहा।

यदि महाकुंभ को दलित समाज के नजरिए से देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भागीदारी केवल सफाई कर्मचारियों के रूप में ही सीमित रही। दुकानों के आवंटन में दलित और आदिवासी समुदाय को नजरअंदाज किया गया, जबकि सफाई के काम के लिए दूर–दराज से दलित समाज के लोगों को काम पर रखा गया। इन दलित सफाईकर्मियों से बेहद कम मेहनताना देकर काम लिया गया, और सुविधा के नाम पर भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। कुछ हजार रुपये कमाने के लिए ये सफाई कर्मचारी दिन–रात मेहनत कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि कुंभ

मेले में दलित समाज की वास्तविक भागीदारी क्या है?

दलितों की तरह मुसलमान भी भेदभाव के शिकार हैं। धार्मिक आधार पर उनके साथ एक तरह से अघोषित भेदभाव किया गया है। मगर जिन मुसलमानों के कुंभ मेले में आने पर एक तरह की रोक लगा दी गई, वही मुसलमान इलाहाबाद पहुँचने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की हर तरह से मदद कर रहे हैं। भगदड़ के बाद भी मुसलमानों ने हिंदू श्रद्धालुओं की सहायता की और सांप्रदायिक नेताओं को यह नसीहत दी कि अलग–अलग मजहब और धर्म होने के बावजूद इंसान सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में एक समान होते हैं। लेकिन हिंदू चरमपंथी संगठन कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को सांप्रदायिक रंग देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जब कि देश–विदेश की मीडिया की नजरें इस भव्य उत्सव पर टिकी हुई हैं, भगवा चरमपंथी संगठन इस आयोजन में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके आर्थिक बहिष्कार की माँग कर रहे हैं।

हालांकि प्रशासन की ओर से मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश से रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में इस बात को लेकर बेचैनी है कि योगी सरकार ने चरमपंथियों के खिलाफ कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। एक लोकप्रिय हिंदी समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ मेले के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते, उनके लिए बेहतर होगा कि वे मेले में न आएं। उन्होंने कहा, 'भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे वे यहाँ पर आयें, उनके लिए कोई रोक–टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुत्सित मानसिकता के साथ यहाँ आता है, तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीकों से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग न भी आएँ तो अच्छा है।'

मुख्यमंत्री योगी ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि मुसलमान कुंभ में आ सकते हैं, क्योंकि वे भी भारत के बराबरी के अधिकार रखने वाले नागरिक हैं और राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। साफ–साफ शब्दों में सांप्रदायिक संगठनों के खिलाफ कोई रुख अपनाने के बजाय, योगी ने उल्टा मुसलमानों (कुत्सित मानसिकता) को चेतावनी दी कि जो लोग सनातन परंपरा का सम्मान नहीं करते, वे कुंभ मेले में न आएं। योगी के अनुसार, अगर कोई मुसलमान संघ द्वारा परिभाषित सनातन धर्म में आस्था नहीं रखता, तो उसका कुंभ मेले में स्वागत नहीं है।

योगी ने यहां तक कहा कि जो लोग हिंदू धर्म की परंपराओं और रिवाजों का पालन नहीं करते, उन्हें मेले में नहीं आना चाहिए, अन्यथा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा सकता है। क्या यह एक प्रकार की धमकी नहीं है? हालांकि उन्होंने यह बात अप्रत्यक्ष रूप से कही है, लेकिन सभी को यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है। अपने इंटरव्यू में योगी ने यह भी कहा कि अगर किसी ने मजबूरी में इस्लाम स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म का सम्मान करता है, तो उसका स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि किसी ने मजबूरी में इस्लाम स्वीकार किया है? दलितों और कमजोर वर्गों के लिए धर्म परिवर्तन मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि यह उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर बार–बार यह बात कहते थे और इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। संघ की विचारधारा के अनुसार, योगी ने यह संदेश भी दिया कि इस्लाम भारतीय संस्कृति और परंपरा से बाहर है।

जहां एक ओर योगी सांप्रदायिक ताकतों को कड़ा जवाब देने में चूंक रहे हैं, वहीं मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि उन्हें केवल उनकी धार्मिक पहचान के कारण मेले में अपनी दुकानें लगाने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। हिंदुत्व विचारधारा वाले संगठन 'अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद' ने मांग की है कि जो लोग गैर–सनातनी हैं, उन्हें कुंभ मेले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही उन्हें मेले के अंदर कोई होटल या दुकान चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। यह संगठन योगी आदित्यनाथ सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का दबाव बना रहा है। मुस्लिम विरोधी माहौल इतना हावी है कि इस संगठन से जुड़े धार्मिक नेताओं ने हिंदू परंपराओं से जुड़े फारसी शब्दों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। उदाहरण के लिए, 'शाही स्नान' में प्रयुक्त 'शाही' शब्द को बदलने की सिफारिश की जा रही है, और जहां–जहां 'पेशवाई' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, उन्हें बदलने की भी वकालत की जा रही है। एक और आरोप यह है कि मुसलमानों

की उपस्थिति या उनके होटल चलाने से कुंभ मेले में कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भगवा चरमपंथियों के निराधार तर्कों के अनुसार, यदि मुसलमान कुंभ मेले के दौरान खाने–पीने की दुकानें खोलते हैं, तो इससे तीर्थयात्रियों की आस्था को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि मुसलमान जानबूझकर भोजन को दूषित करते हैं।

मुस्लिम विरोधी अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि सांप्रदायिक ताकतें कुछ भी कहकर निकल जा रही हैं, लेकिन उन्हें जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने कुंभ मेले के बैनर पर पेशाब किया था। इस अफवाह का उद्देश्य हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करना था, ताकि यह लगे कि मुसलमान उनके पवित्र त्योहार कुंभ को अपवित्र कर रहे हैं। हालाँकि, 11 जनवरी को रायबरेली पुलिस ने स्पष्ट किया कि पेशाब करने वाला व्यक्ति मुस्लिम नहीं, बल्कि एक हिंदू था, जो नशे में था और उसने दीवार के पास पेशाब किया था। यह घटना कुंभ मेले के बैनर के अपमान से संबंधित नहीं थी।

हाल के दिनों में ऐसी कई अफवाहें और वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें मुस्लिम जैसी शक्ल–सूरत या नाम वाले व्यक्तियों को भोजन को दूषित करते हुए दिखाया गया है। भाजपा के बड़े नेता इसे 'थूक जिहाद' कह रहे हैं और इस बहाने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं।

मुस्लिम विरोधी नीतियाँ साफ–सफाई के नाम पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती कि सरकार को होटलों और ढाबों में साफ–सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रबंधन को सफाई में लापरवाही बरतने वाले होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालाँकि, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाना बिल्कुल अनुचित है।

वास्तविकता यह है कि भगवा शक्तियां यह भलीभांति समझती हैं कि जब तक वे मुस्लिम विरोधी विमर्श नहीं फैलाएंगी, उन्हें मुस्लिम विरोधी नीति बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से यह झूठ फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम होटल मालिक जानबूझकर गंदा और अशुद्ध भोजन परोसते हैं। इस प्रचार का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के होटलों को बंद कराकर उनकी व्यापारिक गतिविधियों को हिंदुत्व समर्थक लोगों के हवाले करना है, ताकि मुसलमान आर्थिक रूप से कमजोर और दिवालिया हो जाएं।

कई अर्थशास्त्री यह भूल जाते हैं कि नस्लवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद का व्यावसायिक सफलता और विफलता से गहरा संबंध है। यही वजह है कि होटलों में अकसर दलित कर्मचारी काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन दलितों के नाम वाले होटल बहुत कम दिखते हैं। छुआछूत को कानूनी तौर पर वर्षों पहले समाप्त कर दिया गया है, लेकिन दलितों और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव की मानसिकता अब भी कायम है। जैसे ही किसी संप्रदायवादी को पता चलता है कि किसी दुकान या होटल का मालिक दलित या मुस्लिम है, तो वह उसका बहिष्कार कर देता है। भाजपा सरकार ने धार्मिक श्रद्धा के सम्मान के नाम पर होटल मालिकों को अपनी नेमप्लेट लगाने के लिए मजबूर किया है, जिसका उद्देश्य दलित और मुस्लिम मालिकों की पहचान करके उनके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का रास्ता खोलना है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने जबरन नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश की निंदा की थी, मगर वंचितों को राहत नहीं मिल पाई है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है, और अधिकांश मुसलमान मजदूर या छोटे कर्मचारी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। अगर कुंभ पर्व में संप्रदायवादियों की नापाक महत्वाकांक्षाएं सफल हो जाती हैं, तो छोटे व्यापार में मुसलमानों की उपस्थिति और कम हो जाएगी, और वे सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को हर मोर्चे पर कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सरकार को याद दिलाया जाए कि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में धर्म आधारित नीति नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह, सत्तारूढ़ दल को यह भी स्पष्ट करना होगा कि ईद, दशहरा और क्रिसमस जैसे त्योहार धार्मिक होते हुए भी पूरे समाज द्वारा मनाए जाते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को सांप्रदायिकता और राजनीतिक लाभ के नजरिए से देखना पर्यावरण, समाज और देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। □□

लेखक : स्वतंत्र पत्रकार हैं और नियमित रूप से उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में लिखते हैं।

ईमेल : debatingissues@gmail.com